भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या-347**
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

**क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026**

***347. डॉ. सी. एम. रमेश:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस-डब्ल्यूयूआर) 2026 में अपनी सर्वाधिक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश की उच्च शिक्षा प्रणाली जी-20 देशों में सबसे तेजी से विकसित हो रही है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान क्यूएस-डब्ल्यूयूआर में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और
(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को सर्वोच्च 500 रैंक में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**शिक्षा मंत्री**
**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

****

**माननीय संसद सदस्य डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (घ): उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराना, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

उपरोक्त पहलों को क्रमशः राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रुपरेखा (एनआईआरएफ) द्वारा प्रत्यायन मान्यता और रैंकिंग तंत्रों द्वारा संपूरित किया गया है, जिससे भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को और अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में ढालने में मदद मिली है। परिणामस्परूप शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) सहित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है। यह भारत का अब तक का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है, जो क्यूएसडब्ल्यूयूआर 2015 में 11 संस्थानों से बढ़कर क्यूएसडब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गया है। आठ भारतीय संस्थानों ने पहली बार इस रैंकिंग में प्रवेश किया है, जो इस संस्करण में जी20 के भीतर और वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के लिए सबसे अधिक संख्या है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या पिछले पाँच वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो क्यूएसडब्ल्यूयूआर 2021 में 27 से बढ़कर क्यूएसडब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गई है। इस प्रकार, यह निरंतर नीतिगत पहलों, मजबूत अनुसंधान और नवाचार क्षमता और भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती वैश्विक छवि को रेखांकित करता है।

भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए हैं। वर्ष 2014 से, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और मानविकी के क्षेत्र में नए केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) की स्थापना करके उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन किया गया है। सीएचईआई को क्षेत्र के अन्य संस्थानों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए गति निर्धारक संस्थानों के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2014 से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8

केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की स्थापना एक सर्वोच्च निकाय के रूप में की गई है जो गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु उच्च-स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करेगा। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की पाँच वर्षों की कुल अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपये है।

सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) को भी मंज़ूरी दे दी है। ओएनओएस की परिकल्पना केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के सभी विषयों के छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल समुदाय तक एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से विद्वतापूर्ण शोध पत्रिकाओं की पहुँच का विस्तार करना है। इस योजना के अंतर्गत 6300 से ज़्यादा ऐसे संस्थान शामिल हैं। इस योजना के लिए तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी श्रेणी के 10 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2017 में विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू की थी। अब तक बारह संस्थानों को आईओई के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें 08 सार्वजनिक श्रेणी के संस्थान, अर्थात् - आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और 04 निजी श्रेणी के संस्थान अर्थात्- बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को निधियां मुहैया कराई जाती है। योजना की शुरुआत से 08 सार्वजनिक संस्थानों के लिए 6198.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मंजूर की गई है।

'बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार' (मेरिटे) योजना को 275 तकनीकी संस्थानों में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है, जिनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप मध्यवर्तनों को लागू करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, निष्पक्षता और शासन में सुधार लाना है। यह एक 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' है जिसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए ₹4200 करोड़ है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य, सतत शहरों और कृषि के तीन क्षेत्रों में अंतःविषय अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और मापनीय समाधान तैयार करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, स्वास्थ्य, सतत शहरों और कृषि के क्षेत्रों में एक-एक, कृत्रिम मेधा (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दी है। बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में "शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण" को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक पहल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम 2022, भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षणिक सहकार्यता हेतु ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश हेतु रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं।
- यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शाखा परिसरों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए "यूजीसी (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023" जारी किए हैं। दिनांक 4 अगस्त, 2025 तक, 12 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं।
- शीर्ष भारतीय संस्थानों और प्रमुख विदेशी संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)।
- भारत की शिक्षा प्रणाली में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता लाने के लिए शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (जीआईएएन) योजना। इस योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के वैश्विक प्रतिभा पूल का उपयोग करना तथा देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना है।

*****